आरज़ू-ए-हिन्द
विज्ञापन एवं किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये संपर्क करें
मोबाइल नंबर
8602806746

www.arzooehind.com
RNI No. MPHIN/2017/73229
आरज़ू-ए-हिन्द
साप्ताहिक
एक नई सोच....

वर्ष-09 अंक-05 | भोपाल सोमवार 09 जून 2025 | पृठ-8 मूल्य-2 रूपये

पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज पर लहराया तिरंगा

देश को दी बड़ी सौगात

जम्मू। जम्मू कश्मीर में केंद्र की मोदी सरकार लगातार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आवागमन के बेहतर साधन जुटाने में लगी हुई है। ऐसे ही प्रयासों के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की ऐतिहासिक सौगात दी है। इससे पहले उन्होंने ब्रिज पर पहुंचकर भारत का गौरव तिरंगा लहराया और ब्रिज को काफी देर तक निहारा। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने ब्रिज के जरिए जम्मू और श्रीनगर दशकों के बाद रेल लिंक से जुड़ गया है। कई साल पहले घाटी को देश के अन्य हिस्सों से रेल नेटवर्क से जोड़ने का सपना देखा गया था। अब जाकर वह साकार हुआ है। इससे कश्मीर वैली में न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि व्यवसाय-कारोबार को भी नए पंख मिलने की उम्मीद है।

चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। यह भूकंप के लिहाज से जोन-5 में स्थित है। यह ब्रिज दो पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमेना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज को 260 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। वैष्णव ने बताया कि इस ब्रिज के निर्माण में नींव और मेन स्ट्रक्चर को जोड़ने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इन चुनौतियों को पार किया गया, जिससे यह परियोजना न केवल तकनीकी, बल्कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अनूठा है।

चिनाब और अंजी ब्रिज के निर्माण में भारतीय इंजीनियरों की तकनीकी विशेषज्ञता और इनोवेशन का प्रदर्शन हुआ है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ना सदियों पुराना सपना था, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और अथक प्रयासों से साकार हो रहा है। चेनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इसके साथ ही दो वंदे भारत ट्रेनों का भी लोकार्पण किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगी।

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना को पूरा करना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। जम्मू स्टेशन पर चल रहे काम के कारण वंदे भारत ट्रेनें फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेंगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेनें जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर ऑपरेट होंगी। इस रेल परियोजना में दो इंजीनियरिंग चमत्कार (चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल हैं) जो अत्याधुनिक तकनीक और डिजाइन के प्रतीक हैं।

जी-7 से पहले खालिस्तान समर्थकों ने पीएम मोदी को दी धमकी

सम्मेलन में पीएम मोदी की राजनीति को खत्म कर देंगे

नई दिल्ली,। कनाडा में होने वाली जी-7 समिट से पहले खालिस्तानी आतंकियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि वे इस सम्मेलन में पीएम मोदी की राजनीति को खत्म कर देंगे। कनाडा के खोजी पत्रकार ने यह खुलासा किया है। पत्रकार मोचा बेजिरगान लंबे समय से उत्तर अमेरिका में खालिस्तान समर्थित गतिविधियों को कवर करते रहे हैं। उसने बताया कि, उसे खालिस्तानियों द्वारा धमकाया भी गया। पत्रकार मोचा बेजिरगन ने बताया कि वैंकूवर शहर में साप्ताहिक रैली के दौरान वीडियो बनाते समय उन लोगों ने उन्हें घेर लिया था। मोचा ने बताया कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों का भारतीय नेताओं के प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि वह वैंकूवर में खालिस्तानी समर्थकों की एक रैली को कवर कर रहे थे, उस दौरान उन पर हमला हुआ। खालिस्तानी समर्थकों ने उनका गला दबाने की कोशिश की। फोन छीन लिया और उनको रिकॉर्डिंग करने से रोका। उनके साथ मारपीट भी की। ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ।

पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या सेलिब्रेट कर रहे

पत्रकार ने बताया कि रैली में खालिस्तानी समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट कर रहे थे और कह रहे थे कि वे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की पॉलिटिक्स को जी 7 में खत्म कर देंगे। वे खुद को इंदिरा गांधी के हत्यारों का अनुयायी बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे (खालिस्तान समर्थकों) से पूछा कि क्या आप उनकी राजनीति को उसी तरह खत्म करने जा रहे हैं, जिस तरह आपने इंदिरा गांधी की राजनीति को खत्म किया था? क्योंकि वे हत्यारों को अपने पूर्वज बताते हैं।

वे कहते हैं कि हम इंदिरा गांधी के हत्यारों के वंशज हैं और वे हिंसा के इन कृत्यों का महिमामंडन कर रहे हैं।

मोचा ने कहा कि यह जानकर अफसोस होता है कि कनाडाई नेता इनका साथ दे रहे हैं। वे इनका इतिहास जानते हुए भी ऐसा कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि राजनेताओं को इनसे दूर रहना चाहिए। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड में खालिस्तानी प्रदर्शनों का दस्तावेजीकरण करने वाले बेजिरगन ने कहा कि रविवार को उन्हें डराने धमकाने वाली भीड़ का नेतृत्व एक आंदोलनकारी कर रहा था, जो उन्हें पहले भी ऑनलाइन परेशान कर चुका है।

फिर सुलग उठा मणिपुर : मैतेई लीडर की गिरफ्तारी के विरोध में गाड़ियां फूंकीं} पथराव किया, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट बंद

इंफाल। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। शनिवार को कई जिलों में हिंसा हुई, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगाया गया और पांच जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। शनिवार रात को मैतेई संगठन के अरामबाई तेंगगोल समुह के सदस्यों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने सडकों पर आगजनी की, बसों को आग लगाया और जमकर तोड़फोड़ की। जिसके बाद हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर प्रशासन को आत्मदाह की धमकी दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें कई प्रदर्शनकारी खड़े हैं और खुद पर पेट्रोल डाल रहे हैं। शनिवार देर रात इंफाल ईस्ट और वेस्ट जिलों में उस समय भारी प्रदर्शन शुरू हो गया, जब अरामबाई तेंगगोल समुह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ राजधानी इंफाल के कई इलाकों में झड़पें हुईं। इंफाल के खुराई लामलॉन्ग क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों की गुस्साई भीड़ ने बसें जला दीं, टायर जलाकर सडकें बंद कर दीं और सुरक्षा बलों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके। वो लोग इम्फाल हवाई अड्डे के तुलिहाल के गेट के बाहर एकत्रित हो गए। प्रदर्शनकारियों ने रात को एयरपोर्ट वाली सडक पर यातायात को बाधित किया और वहीं रातभर सोए। उन लोगों को खबरें मिली थी कि गिरफ्तार नेता को बाहर ले जाया जा रहा है। राजधानी इंफाल के कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, सडक़ों पर टायर और पुराने फर्नीचर भी जलाए। सुरक्षाबलों पर पथराव किया। प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने की भी कोशिश की। सरकार ने 7 जून की रात 11:45 बजे से पांच दिनों के लिए 5 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी है। इनमें इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर शामिल हैं। इंफाल ईस्ट और बिष्णुपुर में कर्फ्यू भी लगाया गया है। 3 मई 2023 को कुकी-मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ था, जो आज भी जारी है। इन दो सालों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 1500 से ज्यादा घायल हुए। 70 हजार से ज्यादा लोग विस्थापित हैं। 6 हजार से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं।

खुद को आग लगाने की कोशिश की

मैतेई नेता की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने इंफाल के क्राकेथेल और उरीपोक में सडक़ के बीचों-बीच टायर और पुराने फर्नीचर जलाए। एयरपोर्ट का भी घेराव किया गया। इंफाल के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कुछ प्रदर्शनकारियों ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की।

गुस्साई भीड़ ने इंफाल वेस्ट जिले के खुराई लामलोंग में एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। क्राकेथेल में कई गोलियों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि गोलियां किसने चलाईं। तीन लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। रविवार सुबह भी स्थिति तनावपूर्ण रही।

भोपाल की तीन गोशाला का निरीक्षण कमिश्नर ने किया

कचरे से बायो गैस बनाने का प्लांट देखा बोले-बिजली पानी की अछी व्यवस्था करें

भोपाल। कमिश्नर संजीव सिंह शुक्रवार को जिले की 3 गोशालाओं में पहुंचे। उन्होंने जैविक कचरे से बायो गैस बनाने के प्लांट को देखा। वहीं, पानी और बिजली की व्यवस्था करने को कहा। कमिश्नर सिंह ने बरखेड़ी अब्दुल्ला, बालमपुर और सूखी सेवनिया का निरीक्षण किया। बरखेड़ी अब्दुल्ला में विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत आयोजित वैज्ञानिक कृषक संवाद का निरीक्षण भी किया। संवाद में वैज्ञानिक एमपी सिंह, डॉ. फतेह सिंह, डॉ. सुबीर चक्रवर्ती ने किसानों को उन्नत तकनीक एवं उर्वरकों की जानकारी दी। वहीं, सभी को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी, हैप्पी सीडर के उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। इन व्यवस्थाओं को लेकर बोले कमिश्नर कमिश्नर सिंह ने बरखेड़ी अब्दुल्ला में जीवदया गोशाला एवं निर्माणाधीन सुरभि गोशाला का निरीक्षण किया। निर्देश दिए कि गोशाला में पर्याप्त पानी एवं बिजली की उपलब्धता तय करें। सिंह ने जीवदया गोशाला के संचालक रामदयाल नागर से गोशाला की क्षमता, कार्यप्रणाली, कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज करने की प्रणाली, पानी बिजली की उपलब्धता की चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने किसानों से भी बात की। बरखेड़ी अब्दुल्ला में श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड बायो गैस प्लांट को देखा। अक्षय जैन द्वारा जैव कचरे से बायोगैस बनाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बालमपुर के किसान नारायण सिंह के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वनाधिकार पट्टेधारियों के निर्माणाधीन खेत तालाब का निरीक्षण किया। किसान नारायण ने बताया कि खेत तालाब में 4 लाख लीटर पानी का संचय एवं वाटर रिचार्ज किया जाता है। कमिश्नर संजीव सिंह ने जैविक कचरे से बायो गैस बनने के प्लांट को भी देखा। सूखी सेवनिया में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सुनील जैन के नमन गोल्ड फ्लोर मिल का निरीक्षण भी किया।

मप्र में दिखने लगा पौधारोपण का असरः
अति सघन वनक्षेत्र 356.31 वर्ग किमी बढ़ा

भोपाल, (ए.)। विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरूवार को मप्र सरकार ने इस मानसून सीजन में एक अनोखी और सराहनीय पहल करते हुए 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान शुरू किया है। यह कार्यक्रम 5 जून से प्रदेशभर के स्कूलों में शुरू किया गया। राज्यभर में इस अभियान के तहत 30 सितम्बर तक 50 लाख पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल प्रदेश में अब तक किए गए पौधारोपण का असर दिखने लगा। ताजा आंकड़ों में प्रदेश का अति सघन वनक्षेत्र 356.31 वर्ग किमी तक बढ़ गया है। प्रदेश में 94689 वर्ग किमी का वनक्षेत्र है। इसमें 61886 आरक्षित और 31098 वर्ग किमी का संरक्षित वन है। इस वनक्षेत्र को अति सघन वन, सामान्य सघन वन और खुले वनक्षेत्र में बांटा गया है।

गौरतलब है कि प्रदेश के वनक्षेपत्र को हराभरा करने और ओपन फॉरेस्ट को कम करने हर साल 4 से 5 करोड़ पौधे रोपे जाते हैं। इस पौधारोपण का असर अब दिखने लगा है। पिछले सालों की तुलना में प्रदेश में अति सघन वनक्षेत्र भी बढ़ा है और ओपन फॉरेस्ट भी कम हुआ है। दो साल में 76 वर्ग किमी का ओपन फॉरेस्ट कम हो गया है। यानी लगातार हो रहे पौधारोपण से खुला वनक्षेत्र भी अब हराभरा हो गया है। प्रदेश के पर्यावरण के लिए यह सुखद संदेश है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास संकेत भोंडवे ने बताया कि गुरूवार से प्रारंभ हुए विशेष पौधरोपण अभियान में अमृत योजना के अंतर्गत वृमन फॉर ट्री अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सघन पौध रोपण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे सभी नगरीय निकायों के सहयोग से पूर्ण किया जाएगा। आयुक्त ने नगर वनों के निर्माण, जल संरचनाओं के किनारों पर आठ फीट ऊंचे पौधों के रोपण और थीम आधारित उद्यानों की स्थापना जैसे लक्ष्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि को अतिगिमण से सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण प्रभावी उपाय है।

ओपन फॉरेस्ट घटकर 36543 वर्ग किमी बचा

प्रदेश में साल 2019 में अति सघन वनक्षेत्र 6676 वर्ग किमी का था। साल 2021 में यह वनक्षेत्र 6665 वर्ग किमी का रह गया था। यानी अति सघन वनक्षेत्र भी कम हो गया था। अब अति सघन वनक्षेत्र बढ़कर 7021.31 वर्ग किमी का हो गया है। यानी 356.31 वर्ग किमी का अति सघन वनक्षेत्र बढ़ा है। वहीं साल 2021 में ओपन फॉरेस्ट 36 हजार 619 वर्ग किमी का था, जो अब घटकर 36543 वर्ग किमी का रह गया है। यानी ओपन फॉरेस्ट 76 वर्ग किमी कम हुआ है। साल 2019 से साल 2024-25 तक प्रदेश में 21 करोड़ 78 लाख से अधिक पौधारोपण हुआ। इस पौधारोपण का असर छह साल में नजर आया है, जब प्रदेश में अति सघन वनक्षेत्र बढ़ गया और ओपन फॉरेस्ट कम हो गया है। साल 2024-25 में प्रदेश के वनक्षेत्र में 4 करोड़ 45 लाख से अधिक पौधारोपण हुआ था।

गृह विभाग करेगा भोपाल में शत्रु संपत्ति की जांच

राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय ने किया अधिकृत

भोपाल, । राजधानी भोपाल स्थित शत्रु संपत्ति की जांच अब गृह विभाग द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इसके लिए गृह विभाग के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। यह जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट और क्रिएशन एंड प्रोजेक्शन डॉटकॉम, भोपाल के संचालक अमिताभ अग्निहोत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश एवं भोपाल की समस्त शत्रु सम्पत्तियों की जांच सीबीआई एवं कस्टोडियन विभाग की संयुक्त टीम से कराने की उनकी मांग को स्वीकार करते हुए महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह विभाग भारत शासन के अधिकारियों को अधिकृत किया।

भोपाल नवाब की उत्तराधिकार से संबंधित समस्त चल-अचल सम्पत्तियां भोपाल नवाब की उत्तराधिकारी आबिदा सुल्तान बेगम के पाकिस्तानी

नागरिक होने से भोपाल नवाब की उत्तराधिकार की हैसियत की समस्त चल-अचल सम्पत्तियों को शत्रु सम्पत्ति घोषित करने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कस्टोडियन विभाग नई दिल्ल एवं मुंबई को ज्ञापन भेजा था। इसके साथ ही अग्निहोत्री ने मांग की है बेहटा में नवाब भोपाल की पत्नी द्वारा बेची गई जमीन के मामले को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि आफताब जहां बेगम पाकिस्तानी नागरिक द्वारा भोपाल के बेहटा में बेची गई 30 एकड़ भूमि की जांच के तथ्य 1968 के बाद देश में शत्रु संपत्ति एक्ट लागू होने के बाद क्या पाकिस्तानी नागरिक भोपाल में वर्ष वर्ष 1994-95 में भूमि बेच सकता था, यह भूमि शत्रु सम्पत्ति घोषित क्यों नहीं की गई? क्या जमीन बेचते समय पाकिस्तानी नागरिकता छुपाई गई? वर्ष 1975-76 से देश में अर्बन सीलिंग एक्ट लागू था, तो भोपाल की यह 30 एकड़ भूमि अर्बन सीलिंग में क्यों नहीं ली गई? बेची गई जमीन कितनी राशि में बेची गई एवं बेची गई राशि की रकम किस बैंक से और किस खाते में जमा की गई? वर्ष 1994-95 में जमीन बेचते समय पाकिस्तानी नागरिक आफताब जहाँ बेगम के पासपोर्ट एवं वीजा की भी जांच की जाए।

रीवा के शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन कार्यों की समीक्षा की

पी.के. गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा के सांदीपनि विद्यालय में उन्नयन के कार्यों को प्राथमिकता से करें पूर्ण : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय में रीवा जिले में सांदीपनि विद्यालय और अन्य विद्यालयों के उन्नयन एवं निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पी.के. गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, रीवा को सांदीपनि विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की विशेष चर्चा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि ऑडिटोरियम, खेल सुविधाएँ, फर्नीचर और अन्य निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किए जाएं। जिससे आगामी शैक्षणिक सत्र से सेवाओं का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की तकनीकी अड़चनों को त्वरित रूप से उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा शहर के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के प्रस्तावित उन्नयन कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और

निर्देशित किया कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्रता से पूर्ण कर प्रस्तावों को सक्षम स्तर पर अनुमोदन के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि रीवा शहर से लगे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों के उन्नयन को प्राथमिकता से किया जाये, जिससे इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उन्हें शिक्षा के लिये शहर आने की असुविधा न हो। आयुक्त, स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, पीआईयू, एवं एप्को के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में कैडर बेस होगी कांग्रेस : कांग्रेस को मजबूत करने राहुल गांधी का नया फॉर्मूला

भोपाल। कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। यह फॉर्मूला है कांग्रेस को कैडर बेस बनाना। मप्र में इसकी शुरुआत की जा रही है। अगर ये फॉर्मूला हिट होता है तो पार्टी इसे देश के अन्य राज्यों में भी लागू करेगी। राहुल गांधी के इस फॉर्मूले में पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होंगे जिलाध्यक्ष। जिनकी पार्टी हाईकमान तक सीधी एंट्री होगी। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी इन जिलाध्यक्षों की रजामंदी से होगी। यानी क्षत्रपों की पार्टी कहे जाने वाली कांग्रेस में अब पदाधिकारियों के चयन की पूरी प्रक्रिया बदल रही है। राहुल गांधी की पहल पर चल रही इस कवायद से संदेश साफ है कि अब इस पार्टी क्षत्रपों और पड़ाबाद से बाहर निकलना चाहती है। इसकी शुरूआत जिलाध्यक्षों के चयन से की जा रही है, जिसके लिए कांग्रेस आलाकमान ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। यह इस बात का संकेत है कि आंदोलन से उपजी कांग्रेस क्या भविष्य में कैडर बेस होगी।

मप्र में कांग्रेस की जमीनी हालत की बात करें तो यह खस्ताहाल नजर आती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ की अगुवाई में 15 साल बाद सरकार बनाई और विधायकों की बगावत से पहले, 15 महीने सत्ता में रही। 2023 के चुनाव में जीत के विश्वास के साथ मैदान में उतरी ग्रैंड ओल्ड पार्टी करीब 41 फीसदी वोट शेयर के साथ 230 में से 66 सीटें ही जीत सकी थी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 41.5 फीसदी वोट शेयर के साथ 114 सीटें जीती थीं। कांग्रेस के वोट शेयर में पिछले चुनाव के मुकाबले एक फीसदी से भी कम की कमी आई, लेकिन सीटें 48 कम हो गईं। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन और भी निराशाजनक रहा। 2024 के चुनाम में कांग्रेस खाता खोलने में भी विफल रही। हालांकि, पार्टी को 32.9 फीसदी वोट मिले थे।

गौरतलब है कि कांग्रेस को हमेशा लीडरब्रेस पार्टी माना जाता रहा है। प्रदेश में चार दशक तक सत्ता में रहने वाली यह पार्टी पिछले बीस साल से सत्ता से बाहर है। 2018 में उसकी सरकार बामुश्किल बनी तो पर अंतर्विरोधों के चलते महज 15 महीने में ही गिर गई। लगातार सत्ता से दूरे रहने का असर संगठन पर भी पड़ा है। खासकर पिछले तीन-चार सालों में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी का अलविदा कहा है। इससे पार्टी की साख पर भी असर पड़ा है। राहुल गांधी ने अब मप्र पर फोकस किया है। कांग्रेस नेताओं की

माने तो 2016 में राहुल गांधी ने प्रदेश में संगठन नेताओं की बैठक ली थी, उसके बाद वे किसी रैली या अन्य कार्यक्रम में प्रदेश के दौरे पर तो आए पर संगठन से जुड़े मसलों पर कोई बात कार्यकर्ताओं से नहीं हुई। 3 जून को राहुल गांधी ने छह घंटे से अधिक का समय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बिताया। उन्होंने एक के बाद एक कई बैठकें ली और आला नेताओं से साफ कहा कि अब गुटबाजी नहीं चलेगी। लंगड़े घोड़ों और बारात वाले घोड़ों की चर्चा कर उन्होंने इस बात को भी साफ कर दिया कि अब उम्रदराज नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठाने का समय आ गया है।

राहुल गांधी ने बैठक में उन्होंने साफ कहा कि अब किसी नेता के समर्थक को पद नहीं सौंपा जाएगा। उनका यह कहना कि अब रेस में दौड़ने वाले घोड़े ही हमारे साथ चलेंगे, यह बताता है कि अब पद से लेकर टिकट वितरण में पड़ाबाद नहीं चलेगा। जिलाध्यक्षों के चयन में उसे ही वरीयता मिलेगी जो पार्टी के लिए सच्चे मन से काम कर रहा है। राहुल गांधी जो कहा, उससे यह भी साफ है कि कांग्रेस अब प्रदेश में युवाओं की नई टीम खड़ी करना चाहती है। एक ऐसी टीम जो आने वाले सालों के लिए पार्टी को मजबूती दे। राहुल जानते हैं कि मध्यप्रदेश में तीसरी ताकत मजबूत नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा कर भाजपा को वे आने वाले सालों में तगड़ी चुनौती पेश करना चाहते हैं। पिछले विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में मिली बड़ी पराजय को भुलाकर वे संगठन को ब्लाकस्तर तक मजबूत करना चाहते हैं। जिलाध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया को इसकी शुरूआत माना जा रहा है। राहुल गांधी ने यह कहकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने का प्रयास किया है कि अब टिकट वितरण में जिलाध्यक्षों की राय महत्वपूर्ण होगी। राहुल गांधी की मंशा अच्छी है पर क्षत्रपों में बंटी कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के चयन में स्थापित नेताओं के प्रभाव से पार्टी कैसे अपने आप को बचा पाएगी, यह उसके सामने बड़ी चुनौती है। कांग्रेस की दिक्कत यही है कि उसके पास जो कार्यकर्ता हैं वे पार्टी के कम और नेताओं के प्रति वफादार ज्यादा है। इसी से निजात राहुल चाह रहे है।

मप्र कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या गुटबाजी रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी से लेकर अजय सिंह राहुल तक, मप्र कांग्रेस कई गुटों में बंटी रही है। मप्र चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला, प्रभारी बदला लेकिन आम चुनाव में नतीजा ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती अपनी इकलौती सीट छिंदवाड़ा भी कांग्रेस हार गई। लोकसभा चुनाव में अजय सिंह और गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव लड़ने में असमर्थता जता दी थी। कमलनाथ अपने बेटे की उम्मीदवारी वाले छिंदवाड़ा में भी उतने एक्टिव नहीं दिखे। लोकसभा चुनाव से पहले मप्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह गुटबाजी को कैंसर बताते हुए कहते नजर आ रहे थे कि पार्टी को उबारने के लिए पहले आंतरिक स्तर पर गुटबाजी को खत्म करना ही होगा। मप्र में कांग्रेस की खस्ता हालत के लिए पार्टी के अन्य नेता भी गुटबाजी को जिम्मेदार बताते रहे हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद अनवार अहमद द्वारा एम.आई. आफ्सेट वर्क्स 91, रशीदिया स्कूल के पास, बरखेड़ी, भोपाल से मुद्रित एवं 7, न्यू इतवारा रोड, नवाब मियां की डेरी के पास, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित।
संपादक-सैयद अनवार अहमद मो. 9893338062 कार्यालयः पी.एन.बी. कालोनी, नियर शालीमार बिल्डिंग, ईदगाह हिल्स, भोपाल म.प्र.(सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)